प्रेषक.

सी०एम०एस० बिष्टं. सचिव. उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त जिलाधिकारी. उत्तराखण्ड।

2. मण्डलायुक्त,

गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल उत्तराखण्ड।

4. समस्त विभागध्यक्ष

उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादूनः दिनांक 23 जुलाई, 2014 भारतीय झंण्डा संहिता, 2002, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का विषय:-समुचित अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु महत्वपूर्ण अवसरों पर प्लास्टिक से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2034/XXXI (13)G/2012 दिनांक 04 जुलाई, 2012 एवं संख्या—991 / XXXI(13)G / 12—2013 दिनांक 04 मार्च, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से भारतीय झंडा सहिता, 2002 एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की प्रति प्रेषित करते हुए उक्त अधिनियम का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किथे जाने तथा संगत उपबन्धों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों, संस्थाओं, संगठनों, एवं व्यक्ति विशेष के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं उपर्युक्त विषय के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रायः यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर प्लास्टिक से निर्मित राष्ट्रीय ध्वजों का प्रयोग किया जाता है और समारोह की समाप्ति के पश्चात इधर-उधर फेंक दिया जाता है जिससे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा तो प्रभावित होती है साथ ही प्लास्टिक से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज सरलता से अपघटित न होने से पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इससे भारतीय झंडा सहिता, 2002 एवं राष्ट्रीय गीरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्राविधानों का उल्लघंन भी होता है। भारत सरकार द्वारा भी उक्त स्थिति से बचने के आवश्यक कदम सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता के प्राविधानों के अनुरूप, शासकीय कार्मिकों एवं जनता द्वारा केवल कागज से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जाय तथा समारोह उपरांत कागज निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को न तो विकृत किया जाय और न ही इधर-उधर जमीन पर

फेंका जाय बल्कि ऐसे राष्ट्रीय ध्वजों का निर्दान एकांत में पूर्ण मर्यादा के साथ किया जाय।

कृपया इस शासनादेश की विषयवस्तु को सभी संबंधित अधिकारियों / कार्यालयों के संज्ञान में लाने के साथ ही आवश्यकतानुसार प्रचार-प्रसार भी करने का कष्ट करें।

भवदीय.

(सी०एम०एस० बिष्ट) सचिव।

संख्या- XXXI(13)G/2014तद्दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1-निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-15/3/2014-Public दिनांक 20 जनवरी, 2014 के कम में सूचनार्थ।

2-सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

3-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।

4-सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड।

5-अपर स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।

शासनादेश को राज्य सरकार की वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(वेदीराम ) संयुक्त सचिव।